PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Monday, 31st January 2011, Page: 1
Width: 18.12 cms Height: 14.99 cms, Ref: pmin.2011-01-31.44.1

दवाओं के लिए मरीजों की दिक्कत से सरकार बेखबर

सस्ती दवाएं पाना मरीजों का कानूनी हक, पर डॉक्टर कर रहे हैं अनदेखी

महेंद्र सिंह • नई दिल्ली

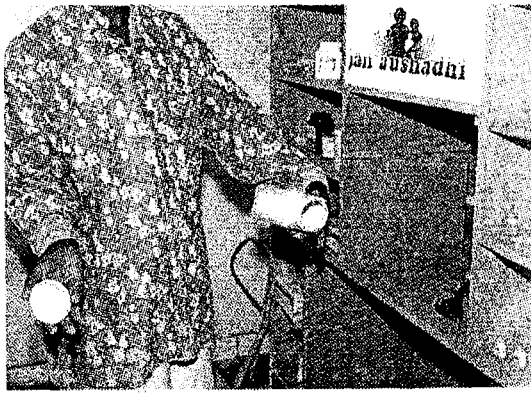

स्थिति सुधरने में लगेगा वक्त

आम तौर पर मरीजों को सस्ती जेनरिक दवाएं नहीं लिखते हैं डॉक्टर

डॉक्टरों को इसके लिए बाध्य करने के वास्ते राज्यों को लिखा गया पत्र

जन औषधि केंद्रों पर दवा सप्लाई के लिए निजी कंपनियों की ली जाएगी मदद

पर निजी कंपनियां जन औषधि योजना को लेकर सरकारी नीतियों पर उठा रही हैं सवाल

जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाओं के लिए आने वाले ग्राहक भले ही खाली हाथ लौट रहे हों, पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधिकारी दवाओं की किल्लत से बेखबर हैं। 'बिजनेस भास्कर' ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में जन औषधि केंद्रों पर जाकर इन केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता के बारे में पड़ताल की तो उसे हर जगह निराशा ही हाथ लगी है। खासकर डॉक्टरों की भारी लापरवाही के कारण ही ऐसी नौबत आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सस्ती दवाएं हासिल करना मरीजों का कानूनी हक है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों एवं सरकार की ओर से इसकी सरासर अनदेखी की जा रही है।

दवाओं की उपलब्धता न होने के सवाल पर जन औषधि के निदेशक रमेश चंद्र झा ने दवाओं की आपूर्ति में दिक्कत की बात स्वीकार करते हुए कहा कि कि जन औषधि केंद्रों को दवा आपूर्ति करने वाली कंपनियां हर राज्य में एक सुपर स्टॉकिस्ट की नियुक्ति कर रही हैं। इससे जन औषधि केंद्रों तक कम समय में दवाओं की आपूर्ति करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा दवाओं की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। यह सॉफ्टवेयर अगले 10 दिनों में काम करना शुरू कर देगा। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया इस सॉफ्टवेयर की मदद से जन औषधि केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता पर नजर रखेगा।

रमेश ने बताया कि जन औषधि केंद्र खुद अपना परिचालन खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं। परिचालन खर्च के लिए यह जरूरी है कि एक केंद्र की मासिक बिक्री कम से कम 3 लाख रुपये की हो, जबकि मौजूदा समय में एक केंद्र की बिक्री 10,000 रुपये से लेकर 30,000 हजार रुपये तक ही है। जन औषधि के निदेशक का कहना है कि डॉक्टर सस्ती जेनरिक दवाएं मरीजों को नहीं लिखते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हमने राज्यों को पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि वे डॉक्टरों को सस्ती जेनरिक दवाएं लिखने के लिए बाध्य करें। रमेश ने बताया कि सरकार जन औषधि योजना को कारगर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। (शेष पेज 12 पर)